



संसद के विशेष सत्र के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला

# महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी

- अब संसद के विशेष सत्र में किया जाएगा पेश
- 13 साल से पेंडिंग हैं महिला आरक्षण बिल
- विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में
- दुनिया की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी



नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र के बीच मोदी सरकार के कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हुई। इससे बैठक के अध्यक्ष का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस

बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस बात की लगातार संभावना जताई जा रही थी कि सरकार कहीं ना कहीं इस विशेष सत्र में कोई बड़ा कदम उठा सकती है। आज यह सही साबित

संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल से यह सत्र नए संसद भवन में आयोजित होगा। इससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान देश की समृद्ध संसदीय विरासत को याद किया जाएगा और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाएगा।

लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा की 33 फीसदी यानी कि एक तिहाई सेट को आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को लेकर लगातार राजनीतिक चर्चाएं तो

सरकार सोमवार से शुरू हुए संसद के पांच दिवसीय सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए जोर नहीं दे सकती है। सूत्रों ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर एक विचार यह है कि विधेयक को कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 10

जारी रहती ही है। यह विधेयक पिछले 27 सालों से पेंडिंग था। इस विधेयक पर आखिरी बार 2010 में कदम उठाया गया था। विधायक को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लिखा कि महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक

साहस मोदी सरकार में ही था। जो कैबिनेट से मंजूरी के बाद साबित भी हो गया। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा का आभार जताया है। तेलंगाना सीएम के.सी.आर. की बेटी के. कविता ने 13 सितंबर को दिल्ली में 13 विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी।

## जीवनसाथी को जानबूझकर शारीरिक संबंध न बनाने देना कूरता: दिल्ली हाईकोर्ट

- 35 दिन ही चला विवाह: हाईकोर्ट
- जीवनसाथी का चरम आस्था धर्म से प्रभावित नहीं हो सकता



नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी का जानबूझकर संबंध बनाने से इनकार करना कूरता है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार अदालत से एक दंपती को मिले तलाक के आदेश को बरकरार रखा। उनकी शादी सिर्फ 35 दिन ही चली थी। वहीं एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जीवनसाथी का चरम आस्था, धर्म से प्रभावित नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने ही एक मामले के

फैसले में संबंध के बिना शादी को एक अभिशाप बताया है। किसी वैवाहिक बंधन में यौन संबंध का न होना काफी घातक स्थिति है। इस मामले में भी पत्नी के विरोध की वजह से विवाह संपूर्ण ही नहीं हुआ। पीठ ने यह भी कहा कि महिला ने पुलिस में यह भी शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे दहेज के लिए परेशान किया गया। जबकि कोई ठोस सबूत नहीं था। इसे भी बरूता कहा जा सकता है। उसने यह कहते हुए तलाक देने के परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ पत्नी

## सुसाइड हब बना कोटा अब यूपी की छात्रा ने जहर खाकर दी जान

जयपुर। राजस्थान के कोटा में छात्र-छात्राओं के सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर छात्रा के सुसाइड का मामला सामने आया है। सोमवार को यूपी के मऊ की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। मऊ निवासी 17 वर्षीय छात्रा ने कोटा में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। छात्रा प्रियम सिंह कोटा में पिछले डेढ़ साल से रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। सोमवार को कोचिंग संस्थान के बाहर शाम को छात्रा उल्टी करती हुई नजर आई तो अन्य छात्रों ने कोचिंग संचालक को सूचना दी। छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि छात्रा ने कोचिंग जाने से पहले सल्फास का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कोचिंग संस्थान के बाहर उल्टियां कीं।

## गौड़ा में प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का मुख्यमंत्री योगी ने किया उद्घाटन

# यूपी में निवेशकों को सुरक्षा व हर तरह की सुविधा की गारंटी: योगी



अवधनामा संवाददाता

- पूरे देश में विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सकारात्मक माहौल: योगी
- उप में बेहचक निवेश करें, सरकार साथ खड़ी मिलेगी

इंसेटिव प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक माहौल बना है। यह सकारात्मक माहौल विकास, सुरक्षा व समृद्धि का है। जब प्रत्येक व्यक्ति के एजेंडे में विकास होता है तो वह हर तरीके से उसके लिए माहौल बनाने में अपना योगदान देता है। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और, उसमें भी आज से पांच-सात साल पहले गोरखपुर की स्थिति क्या हुआ करती थी। अपराध और माफिया हर एक व्यवस्था पर हावी था। अराजकता चरम पर रहती थी। प्रदेश में हर दूसरे-तीसरे दिन एक दंगा होता था। भ्रष्टाचार चरम पर था। इस माहौल में राज्य के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। विकास कार्य तब हो गए थे। असुरक्षित वातावरण में कोई निवेश नहीं



यूपी को मिले हैं 36 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश को 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अकेले गोरखपुर को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर एक करोड़ नौजवानों को नौकरी व रोजगार मिलने की संभावना है। गौड़ा में 102 नए उद्योगों की स्थापना के लिए आशय पत्र के वितरण का कार्य इसी संभावना को आगे बढ़ाएगा।

सहजनावा से धुरियापार तक हो रहा गौड़ा का विस्तार

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज गौड़ा का व्यापक विस्तार हो रहा है। सरकार इसे सहजनावा से धुरियापार तक ले जा रही है। अकेले धुरियापार में 5000 एकड़ से अधिक में उद्योग लगाने के लिए एक व्यापक पैमाने पर कार्यरत हो रहे हैं। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यहीं पर रोजगार और नौकरी उपलब्ध हो सकेगी। विकास का जो सकारात्मक माहौल उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के अंदर बना है, उसका लाभ यहां के लोगों को प्राप्त होगा।

लगभे 102 उद्योग, 900 करोड़ का होगा निवेश

गौड़ा सेक्टर 26 में आयोजित समारोह में सीएम योगी की मौजूदगी में 97 निवेशकों/उद्यमियों को 102 भूखंडों का आवंटन पत्र वितरित किया गया। 14 निवेशकों को भूखंड आवंटन पत्र मुख्यमंत्री के हाथों से प्राप्त हुआ। इन 102 भूखंडों पर अलग अलग यूनिट लगाने से करीब 900 करोड़ रुपये का निवेश होगा और निवेश के धरातल पर उतरने से करीब 4500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 102 उद्योगों के लिए जमीन का आवंटन हो चुका है।

इंजन की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में आज सभी लोगों ने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है।

## अयोध्या में श्रीराम पथ के गेट और कनोपी के निर्माण में लापरवाही

- महाप्रबंधक व प्रोजेक्ट मैनेजर पर गिरी गाज



लखनऊ। अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि पथ के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले राजकीय निर्माण निगम के महाप्रबंधक अजय मिश्रा व परियोजना प्रबंधक अनूप शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की थी। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने दोनों अधिकारियों के निलंबन की पुष्टि की है। श्रीराम पथ पर मुख्य द्वार के खंभे बनाने के साथ मार्ग पर दोनों तरफ 10 कनोपी बनाने का काम राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया है। 13 करोड़ रुपये के इस काम को करवाने के लिए निविदा

निकालने में देरी किए जाने से लेकर निर्माण कार्य शुरू करवाने में की गई लापरवाही का आरोप दोनों अधिकारियों पर है। नौ सितंबर को श्रीराम जन्मभूमि के महासचिव नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया था। इसी दौरान उन्होंने पथ के निर्माण स्थल का भी दौरा किया तो जगह-जगह पर खोदे गए गड्ढे देखकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। पथ पर कनोपी का निर्माण करवाने के लिए खोदे गए गड्ढे के बारे में महाप्रबंधक व परियोजना प्रबंधन

## एमएसपी के लिए होगा बड़ा आंदोलन: टिकैत

लखनऊ के ईको गार्डन में आयोजित किसान मजदूर अधिकार महापंचायत का ऐलान

- फसल और नस्ल दोनों बर्बाद कर रही सरकार
- किसानों की लाठी का दम कम नहीं हुआ है
- 2027 तक तो नहीं लगने देंगे बिजली मीटर



लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर गांटी कानून की मांग को लेकर पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा। सरकार अपने वायदे से मुकर गई है। बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर फसल और नस्ल दोनों को बर्बाद करने पर तुली है। सोमवार को राकेश लखनऊ के ईको गार्डन में आयोजित किसान मजदूर अधिकार महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की जमीन

मुफ्त में लेने का षडयंत्र चल रहा है। रात के अंधेरे में जमीन बिक जाती है पर दिन के उजाले में किसानों को फसल नहीं बिक पाती। अधिकारियों और नेताओं ने तमाम हाइवे के किनारे की पूरी जमीन खरीद ली है। पूरे देश का किसान परेशान है। आलू किसान जमाखोरों से, गन्ना किसान मूल्य कम और भुगतान न होने से परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव दोनों से ही कम गन्ना मूल्य वर्तमान मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है। व्यापारी फसलों की भी कालाबाजारी कर रहे हैं। कश्मीर के सेव किसानों के सेव से लंदे टुक जानबूझकर 15 से 22 दिन रोके गए जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। लखनऊ के किसानों की जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहीत की गई थी पर आज तक उन्हें एक रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। युवा भाकियू अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा कि किसानों की लाठी का दम कम नहीं हुआ है। समय आने पर यह बता दिया जाएगा। विभिन्न

ज्ञापन में दी गई मुख्य मांगें

सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, मीटर लगवाने की प्रक्रिया रोकने, गन्ना मूल्य 500 रुपये क्विंटल घोषित करने, गन्ना बकाया देने, सरकारी जमीन पर पशुशाला बनाने, किसान आयोग का गठन, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एनजीटी के नियमों में ढील, लखीमपुर कांड के दोषियों को सजा देने, बाढ़- सूखे का सर्वे कराकर मुआवजा देने, ऋण माफ करने, सोलानी नदी पर बांध बनाने, जीएम सरसों को प्रतिबंधित करने आदि की मांग की गई।

मांगों को लेकर सीएम को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा, पवन खटाना, राजवीर सिंह जादौन समेत विभिन्न जिलों से आए किसान मौजूद थे। राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को बिजली मुफ्त में देगा। ऐसे में वर्ष 2027 तक तो प्रदेश में मीटर नहीं लगाने दिए जाएंगे।





























